



पायलियर

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

www.dailypioneer.com



हरिवंश ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चेताया राष्ट्रीय-11

कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ऐलान आज

खरगे के साथ कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने बैठक कर रिपोर्ट सौंपी, पार्टी अध्यक्ष राज्य और केंद्र के नेताओं से बातचीत करने के बाद उचित फैसला लेंगे

● सिद्धरमैया व शिवकुमार में किसी एक को चुनने के लिए जद्दोजहद से गुजर रही पार्टी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली। बंगलुरु



बंगलुरु से दिल्ली रवाना होते कांग्रेस नेता सिद्धरमैया

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए दो दावेदार के सिद्धरमैया तथा लोकप्रिय नेता डीके शिवकुमार के बीच किसी एक को चुनने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को कड़ी जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है। उंट किस करवट बैठेगा इसको लेकर संभ्रम बरकरार है। सोमवार देर शाम तक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर कई दौर की बैठकें चली लेकिन बेतरीजा रहीं। पूरे दिन बेचैनी भरा माहौल बना रहा। बहरहाल खरगे के घर पर बैठक के बाद देर रात कर्नाटक के पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 6.5 करोड़ कनडवासियों के साथ खड़ी है। पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, वे राज्य के नेताओं और अन्य केंद्रीय नेताओं से बातचीत के बाद उचित कदम कदम उठाएंगे। सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी मंगलवार शाम तक अपने फैसले का ऐलान करेगी। इससे पहले विधायक

दल का नेता चुनने को लेकर नवनियुक्त विधायकों की राय जानने के बाद तीनों पर्यवेक्षकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की और ऐसे में पूरी निगाहें पार्टी आलाकमान पर टिक गई हैं।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी के तीनों पर्यवेक्षकों ने खरगे को रिपोर्ट सौंप दी है और फिर खरगे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। तीनों पर्यवेक्षकों ने पार्टी के नवनियुक्त विधायकों से अलग-अलग बात कर उनकी राय जानी थी।

ये तीनों पर्यवेक्षक सोमवार शाम खरगे के आवास पर पहुंचे। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज दिन में दिल्ली पहुंच गए और उनके भी खरगे से मुलाकात करने की संभावना है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के कमेटी अध्यक्ष डी के शिवकुमार भी सोमवार को दिल्ली आने वाले थे, लेकिन पेट में संक्रमण का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी। दोनों नेता मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। विधायकों की राय जानने के लिए बंगलुरु भेजे गए पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक सोमवार को दिल्ली लौट आए। विधायकों की राय जानने के लिए गोपनीय मतदान भी कराया गया है। तीनों पर्यवेक्षकों ने बंगलुरु के एक निजी होटल में रविवार रात कई घंटे तक विधायकों के साथ बातचीत की और अगले मुख्यमंत्री को लेकर गोपनीय मतदान भी कराया गया है। शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, हमारी रिपोर्ट (कांग्रेस विधायक दल को बैठक में मिली प्रतिक्रिया पर आधारित) गोपनीय है, जिसका खुलासा हम नहीं कर सकते। हमारे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ही

शिवकुमार आज दिल्ली आएं, पहले यात्रा कर दी थी रद्द एजेंसी। बंगलुरु

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दावेदार एवं कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख डी.के. शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे और नेताओं से बातचीत करेंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी थी, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इस पद को दावेदारी के मुद्दे पर पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं है। हालांकि, उन्होंने सोमवार को यात्रा रद्द करने से कुछ ही घंटे पहले इस बात की पुष्टि की थी कि वह राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने वाले हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की योजना में बदलाव के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। राज्य में



गठित होने वाली कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, उसे लेकर शिवकुमार की पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ रसाक्षकी चल रही है। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, मेरे पेट में कुछ समस्या है। इसमें जलन हो रही है। ऐसा लगता है कि कुछ संक्रमण हो गया है और मुझे बुखार है...मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए...। उनके करीबी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि वह आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं।

इसका खुलासा कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कुछ विधायकों ने विधायक दल को बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी पसंद बताई, हालांकि विधायक सबके सामने अपनी पसंद बताने में हिचक रहे थे, जिसके बाद उन्हें लिखित रूप से अपनी राय बताने के लिए कहा गया। (शेष पेज 9)

पायलट का अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम

● पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा- व डरने या दबने वाले नहीं, मांगें पूरी न हुई तो पूरे राज्य में छेड़ेंगे आंदोलन

पायनियर समाचार सेवा। जयपुर



जयपुर में जनसंघर्ष पट्टाया के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट

राजस्थान की पूर्व भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के बहाने गहलोल सरकार पर लगातार हमलावर सचिन पायलट आरपार के मूड में आ गए हैं। राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री पायलट ने अपनी ही पार्टी की सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वह पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ देंगे। राजधानी जयपुर में पांच दिवसीय जनसंघर्ष पट्टाया के समापन के मौके पर एक रैली में कांग्रेस के 14 विधायकों के साथ असंतुष्ट नेता सचिन पायलट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोल की अगुआई वाली सरकार को खुली चेतावनी दी। पायलट ने कहा कि उनकी मांगें हैं, जिनमें राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) को बंद कर इसका पुनर्गठन करना, पेपर लीक से प्रभावित प्रत्येक नौजवान को उचित आर्थिक मुआवजा देना और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच करना शामिल है।

आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन प्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह आम धारणा है कि यहां जुगाड़ काम करता है और नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं। सचिन पायलट ने स्पष्ट कहा कि अभी तक उन्होंने गांधीवादी तरीके से एक दिवसीय अनशन किया और पांच दिनों जनसंघर्ष यात्रा निकाली है। महीने के आखिर तक यदि कार्रवाई नहीं होती है तो वह पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी पद पर रहें या न रहें, राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपने आखिरी सांस तक करते रहेंगे। वह डरने वाले नहीं हैं, न ही वह किसी से दबने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के विरोध में है।

गहलोल गुट पर परोक्ष रूप से तीखा हमला करते हुए पायलट ने कहा कि जो भी (कांग्रेस नेता) गुटबाजी व पार्टी में अनुशासन की बात करते हैं, उन्हें 25 सितंबर 2022 की घटना के दिनों जनसंघर्ष यात्रा निकाली है। कि उस दिन जो विश्वासघात किया गया सोनिया गांधी के साथ, पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया गया, जिसमें पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरवां में झांकर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमें तोड़ा या किसी और ने तोड़ा। जनसभा में मंच पर पायलट समेत कांग्रेस के कुल 15 विधायक मौजूद थे। (शेष पेज 9)

जहां कांग्रेस मजबूत, वहां उसको समर्थन देंगे: ममता

● पहली बार बनर्जी ने विपक्षी एकता के लिए संभावित रणनीति पर तृणमूल कांग्रेस के रुख को लेकर साफ की स्थिति

पायनियर समाचार सेवा। कोलकाता



राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अन्य दलों का भी समर्थन करना होगा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रियो ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें उम्मीद है कि सीट बंटवारे के फार्मूले में उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां वे मजबूत हैं। उन्होंने कहा, मजबूत क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बनर्जी ने संभावित रणनीति पर तृणमूल कांग्रेस के रुख को लेकर स्थिति साफ की है। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, जहां भी कांग्रेस मजबूत है, उन्हें लड़ने दीजिए। हम उन्हें समर्थन देंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उन्हें अन्य

मुख्यमंत्री आवास की जांच कर रहे अफसर से सभी काम वापस लिए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● नौकरशाह पर जबरन वसूली रकैट चलाने का आरोप, उनके कमेटी से रिपोर्टें जमा करने के निर्देश

नौकरशाहों और दिल्ली मंत्रिमंडल में बढ़ते गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंपाईकरण के मामले में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव (सतर्कता) वार्डवीवीजे राजशेखर से सारा काम वापस लेने का आदेश दिया है। साथ ही उनके कमेटी से रिपोर्टें जमा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 13 मई को राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रकैट चलाने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया। सूत्रों ने कहा कि राजशेखर कथित दिल्ली शराब घोटाले और मुख्यमंत्री के बंगले के सौंपाईकरण की जांच कर रहे सतर्कता अधिकारी हैं। वह दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उदित प्रकाश द्वारा अपने लिए एक विशाल बंगला

बनाने के वास्ते विरासत स्मारक को गिराए जाने की भी जांच कर रहे हैं। अधिकारी ने आधिकारिक नोट मिलने की पुष्टि की है। राजशेखर ने कहा कि मंत्री के सौंपे के संबंध में मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट भेज दी है। आधिकारिक नोट के मुताबिक, ऐसी शिकायतें हैं कि राजशेखर जबरन वसूली का रकैट चला रहे हैं और रांदादारी की मांग कर रहे हैं। यह आरोप काफी गंभीर है, जिसकी विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, राजशेखर को सौंपे गए सभी कार्य वापस लिए जाते हैं।

इसमें कहा गया है कि इसे सहायक निदेशकों के बीच वितरित किया जा सकता है और सहायक निदेशक सीधे सचिव (सतर्कता) को रिपोर्ट करेंगे। सहायक निदेशकों को फाइल को सीधे सचिव (सतर्कता) को भेजना चाहिए। यह अगले आदेश

तक तत्काल अनुपालन के लिए है। सूत्रों ने कहा कि भाद्राज ने यह भी निर्देश दिया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी राजशेखर के कमेटी से रिपोर्टें जमा किए जाएं। यह कदम पिछले सप्ताह केजरीवाल द्वारा आगामी दिनों में बड़े स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल की घोषणा और सार्वजनिक कार्यों में बाधा पैदा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी के मद्देनजर आया है। दिल्ली सरकार ने आईएएस अधिकारी और सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे के खिलाफ उनके स्थान पर एक नए अधिकारी को नियुक्त करने के उसके निर्देश का पालन नहीं करने पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और तैनाती पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिए जाने के कुछ घंटों बाद दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते मोरे को उनके पद से हटा दिया था।

बजरंग दल पर टिप्पणी खड़गे को नोटिस जारी

पायनियर समाचार सेवा। संगरूर

बजरंग दल के खिलाफ टिप्पणी और कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में इसकी तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करने के मामले में स्थानीय अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि मामला दर्ज कराया गया है। अदालत ने 12 मई को जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जुलाई को तारीख तय की है। हिंदू सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारद्वाज ने अपनी याचिका में दलील दी है कि प्रतिवादी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 2 मई को कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इसमें बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की घोषणा की और इसकी तुलना पांपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठन से कर अपमानजनक बयान दिए। गंग ने कहा कि पीएफआई से तुलना किए जाने से बजरंग दल और हिंदू सुरक्षा परिषद के करोड़ों सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंची है तथा इसने भावना हनुमान के आराधकों की भी मानहानि की है।

गुरुद्वारा परिसर में शराब पीने पर महिला की हत्या

● एसजीपीसी ने बेअदबी की घटनाओं को सिखों के विरुद्ध सोची-समझी साजिश बताया

पायनियर समाचार सेवा। पटियाला

शहर पटियाला के एक गुरुद्वारे में कथित तौर पर शराब पीने पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पुलिस से कहा कि बेअदबी के कारण धार्मिक भावनाएं आहत होने पर वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। मृतक महिला को पहचान परिवंदर कौर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच है। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वरुण शर्मा ने कहा कि महिला रविवार को दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे के सरोवर के पास कथित रूप से शराब पी रही थी। उसी समय गुरुद्वारे में नियमित रूप से आने वाले निर्मलजीत सिंह सैनी ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने

आधिकारिक बयान में कहा कि सैनी ने 32 बोर की अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से महिला पर पांच गड्डे गोलियां चलाईं। परिवंदर को तीन गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी ने स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपना हथियार उन्हें सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले सैनी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने अमृतसर में जारी एक बयान में कहा कि सिख विरोधी ताकतें सोची-समझी साजिश के तहत गुरुद्वारा साहिब को निशाना बना रही हैं, जबकि सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पटियाला में ऐतिहासिक गुरुद्वारे के अंदर महिला के शराब पीने की शरारतपूर्ण हरकत एक साजिश है, जो अचानक हुई घटना नहीं हो सकती। (शेष पेज 9)

विवक न्यूज

अब रेलवे स्टेशनों पर लगे एक जैसे संकेतक

नई दिल्ली। यात्रियों की आसानी के लिए भारत भर के रेलवे स्टेशनों पर संकेतकों को रंग, फॉन्ट और चित्रलेखों के उपयोग के आधार पर मानकीकृत किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैशाव ने सोमवार को पटियाला के विवरण से संबंधित एक प्रेस विज्ञापन पर यह बात कही। अतुल भारत स्टेशन योजना के तहत भारत में 1,275 स्टेशनों का पुनर्विचार कर रेल भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के वास्ते सभी स्टेशनों पर एक समान संकेत लगाने का प्रयास करेगा। वैशाव ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेल रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। यह महसूस किया गया कि स्टेशनों पर संकेतों पर मानक दिशानिर्देश जारी किए जाएं जो सुगम और पर्याप्त होंगे। रेल मंत्री ने कहा, आज मुझे भारतीय रेल के स्टेशनों पर मानक संकेत के वास्ते प्रेरितवा जारी करते हुए खुशी हो रही है। भारतीय रेल आधुनिक, मानक संकेतों को अपनाएगा, जो दिवंगम के अनुकूल है।

शाह ने मणिपुर हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई को कहा

● केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मेइती और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

भाषा। नई दिल्ली



इंफाल में प्रकारों को संबोधित करते मुख्यमंत्री (एन बीरेन सिंह मध्य में)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मणिपुर में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और स्थानीय शांति सुनिश्चित करने में राज्य को केंद्र की ओर से पूर्ण समर्थन दिए जाने का आश्वासन दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मेइती और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें करके राज्य में शांति बहाल करने के लिए पिछले दो दिन में उठाए गए कदमों की समीक्षा की,

जिसके बाद ये निर्देश जारी किए। बयान के अनुसार, उन्होंने सभी गुटों से चर्चा करने और शांति का संदेश देने का भी आग्रह किया और न्याय का आश्वासन दिया। शाह ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया और स्थानीय शांति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और मदद का आश्वासन दिया। बयान के अनुसार, गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य में विभिन्न समुदायों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएगी। बयान में कहा गया है कि उन्होंने राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया, ताकि लोगों की पीड़ा को कम किया जा सके। बैठकों के दौरान, गृह मंत्री ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की, जहां दो जातीय समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। बैठक में मौजूद लोगों में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अलावा मणिपुर के चार कैबिनेट मंत्री और राज्य से एक राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। (शेष पेज 9)

जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर, अन्यथा होगी कार्रवाई: केंद्र

● केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों को निर्देश, दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के आने पर भी रोक लगाने को कहा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली



केंद्र ने अपने सरकारी अस्पतालों एवं केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत आने वाले आरोग्य केंद्रों के चिकित्सकों को चेतावनी दी है कि वे मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयों लिखने के नियम का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने चिकित्सकों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पतालों में मेडिकल रिजर्जेंटिव (दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों) के आने पर रोक लगाई जाए। सरकार के आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के अस्पतालों, सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों और पॉलीक्लिनिक के

चिकित्सकों को समय-समय पर निर्देश दिया गया है कि वे केवल जेनेरिक दवाएं ही लिखें। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल ने 12 मई को जारी एक आदेश में कहा, इसके बावजूद, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में (रेजिडेंट सहित) चिकित्सक अब भी ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। आदेश के अनुसार, सभी संस्थानों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने अधीन काम करने वाले चिकित्सकों द्वारा इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इसमें कहा गया है कि आदेश

का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर, सभी चिकित्सकों को अब राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएससी) में पंजीकरण करना होगा और देश में प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) मिलेगी। एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, इन आंकड़ों को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में अद्यतन किया जाएगा और यह आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा तथा एनएससी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। वेबसाइट पर

चिकित्सक के बारे में विभिन्न जानकारी होगी जैसे पंजीकरण संख्या, नाम, पंजीकरण की तिथि, कार्यस्थल (अस्पताल या संस्थान का नाम), अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता सहित चिकित्सा योग्यता, विशेषता और उन संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम जहां चिकित्सक ने पढ़ाई की थी। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिन्होंने 2019 चिकित्सा आयोग कानून 2019 के तहत मान्यता प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है और अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वह एनएमआर में पंजीकरण के लिए पात्र होगा। अधिसूचना के अनुसार, विदेशों से चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले और अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक भी एनएमआर में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे विदेशी चिकित्सा स्नातक विनियमन, 2021 की शर्तों को पूरा करते हों।

प्रदूषण स्रोतों का पता लगाएगी मोबाइल वैन

हॉटस्पॉट बिंदुओं पर तैनात होगी, रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी पर विशेषज्ञों के सुझाव से बनेगी कार्ययोजना

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

पर्यावरण को बेहतर बनाने की एक और पहल शुरू की गई है। शहर में वायु प्रदूषण के स्रोतों की वास्तविक समय में पहचान करने के लिए हुए अध्ययन के नतीजों और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की रणनीति बनाने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ गोलमेज सम्मेलन किया।



राजधानी में प्रदूषण मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ गोलमेज सम्मेलन में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय।

यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमडी, डीआरआईआईवी, सीएसई, एमसीडी आदि विभागों और संस्थाओं के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल रहे। गोपाल राय ने राउंड टेबल कांफ्रेंस के बाद सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को कम

करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण में 30 फीसद की कमी दर्ज की गई है। हर साल गर्मी और सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए समर और विंटर एक्शन प्लान लागू किए जाते हैं। विंटर एक्शन प्लान के हिस्से के रूप में रियल टाइम

● 13 हॉटस्पॉट पर एक हफ्ते के लिए मोबाइल वैन तैनात करने के निर्देश जारी

सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी को शामिल किया था। इससे प्रदूषण के कारणों का पता चल रहा है। ऐसा करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है।

रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी से हर घंटे पता चल रहा है कि कहां, किस वजह से प्रदूषण है और अगले 3 दिन का घंटे के आधार पर फोरकास्ट का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इससे सरकार को किसी भी इलाके में वाहन, इंडस्ट्री, बायोमास बर्निंग, धूल आदि की वजह से होने वाले प्रदूषण को सही सही जानकारी

प्राप्त हो रही है। उन्होंने रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पहले वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों को पता लगाने की प्रक्रिया काफी लंबी और मेहनती होती थी वहीं आज रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी के कारण अब वायु गुणवत्ता की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और मौसमी विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। इस सुपरसाइट के कारण सरकार को वायु प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देने वाले पीएम 2.5, एनओ2, एनओ एक्स, सीओ, एसओ2, ओजोन, सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एंड आर्गेनिक ऐरोसॉल्स की निगरानी आसान हो गया है। साथ ही मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को 13 हॉटस्पॉट पर एक एक हफ्ते स्थापित करने के निर्देश जारी किये गए हैं।

कारण बताओ नोटिस के बाद अचानक सचिवालय पहुंचे मोरे

● सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने पर जताई सहमति, पहले आप सरकार की ओर से नए सर्विसेज सेक्रेटरी की नियुक्ति को मानने से किया था इनकार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कई दिनों से गायब दिल्ली के सर्विसेज सेक्रेटरी आधिकारिक सोमवार को अचानक सामने आ गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने पर सहमत हो गए। सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के

रिविल सेवा बोर्ड की बैठक आज

दिल्ली सरकार के नौकरशाहों तबादले और तैनाती के निर्देश के अनुसरण में और सर्वोच्च न्यायालय की सविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर मुख्य सचिव ने मंगलवार को सिविल सेवा बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में अधिकारी इस बात पर चर्चा करेंगे कि वह जीएनसीटीडी को रिपोर्ट करेंगे न कि उपराज्यपाल को उसी पर मंथन होगा।

आदेश नहीं मानने पर अवमानना

दिल्ली सरकार को सेवा मामलों पर नियंत्रण देने वाला उच्चतम न्यायालय का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका अनुपालन नहीं करने वाला अधिकारी अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा। दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत के फैसले के बाद सेवा विभाग ने कानून विभाग की राय मांगी थी।

लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए

कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद उनके व्यवहार में अचानक यह बदलाव आया। मंत्री द्वारा आशीष मोरे की जगह नए सर्विसेज सेक्रेटरी की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी उन्होंने अवहेलना की थी। निर्देश दिए

जाने पर अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों को छोड़कर आशीष मोरे रहस्यमय तरीके से दिल्ली सचिवालय से गायब हो गए थे। संबंधित अधिकारियों द्वारा संपर्क किए जाने पर उनकी पत्नी ने कहा था कि उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सत्येंद्र जैन की सेल में दो कैदी भेजने पर मचा बवाल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जैन की सेल में दो कैदियों को स्थानांतरित करने को लेकर जेल नंबर सात के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले जैन की मांलिश को लेकर बवाल मचा था। तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने बताया कि सत्येंद्र जैन ने जेल प्रशासन को एक अर्जी दी थी जिसमें कहा गया था कि वह अकेलापन महसूस कर रहे हैं और

● तिहाड़ महानिदेशक संजय बेनीवाल ने अधीक्षक को नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण

अवसाद में हैं अतः उनके साथ दो कैदियों को रखा जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधीक्षक ने इस मामले में प्रशासन को जानकारी दिए बिना अथवा विचार-विमर्श किए बिना कैदियों का स्थानांतरण किया। उन्होंने कहा कि जब जेल प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो संबंधित पुलिस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने कैदियों को वापस उनकी सेल में भेज दिया।

● बेहतर होगा जैन सरकारी गवाह बन जाए : भाजपा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेव ने कहा है वह यह जानकर स्तब्ध हैं किगत दिनों सत्येंद्र जैन ने अपनी इच्छानुसार कैदी चुनकर अपनी बैरक में सेवा के लिए रखवा लिये। इस एक घटना से स्पष्ट होता है कि तिहाड़ में किस तरह केजरीवाल के पूर्व मंत्रियों के मनमानी का खेल चल रहा है। सचदेव ने दावा किया कि उनकी जानकारी में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसी तरह बहुत सी सुविधाएं पा रहे हैं। वीरेन्द्र ने कहा कि वह नहीं जानते कि जैन ने किन दो कैदियों को अपने साथ रहने के लिए चुना है। पर जब उनके पास साथी चुनने की छूट थी ही तो बेहतर होता वे मनीष सिसोदिया और सुकेश चंद्रशेखर को चुन लेते ताकि तीनों साथ बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते रहते।

अधिकारी के अनुसार, महानिदेशक संजय बेनीवाल ने तिहाड़ जेल की जेल नंबर सात के अधीक्षक को दिशानिर्देशों का पालन किए बिना दिल्ली के पूर्व मंत्री के सेल में कैदियों को स्थानांतरित करने तथा यह कदम उठाने से पहले जेल

डीबीएसई ने पहली बार घोषित किया 10वीं, 12वीं का परिणाम

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

शिक्षा मंत्री आतिशी ने पहली बार सोमवार को दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड (डीबीएसई) की 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए। मंत्री ने बताया कि 10वीं कक्षा के 1,594 विद्यार्थियों में से 1,582 विद्यार्थी दोनों सत्र की परीक्षाओं में उपस्थित हुए और आठ विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक तीन ग्रेड अंक हासिल नहीं कर पाए। शिक्षा मंत्री आतिशी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जो विद्यार्थी आवश्यक ग्रेड अंक हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें एक



महीने बाद अंकों में सुधार लाने का एक और मौका दिया जाएगा। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 672 छात्रों ने पंजीकरण कराया और 667 छात्र दोनों सत्रों की परीक्षा में उपस्थित हुए। बारहवीं कक्षा के जो पांच छात्र तीन ग्रेड अंक हासिल नहीं कर पाए, उन्हें प्रदर्शन में सुधार लाने का एक अवसर दिया जाएगा।

थप्पड़ का बदला लेने के लिए युवक की हत्या, गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

युवक की हत्या के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गुजरात अपराध शाखा के साथ मिलकर हत्या के आरोपी को गुजरात से धर दबोचा है। आरोपी ने सात मई को थप्पड़ का बदला लेने के लिए युवक की हत्या कर भाग गया था। इसके बाद उसने पिता को मजदूर के नंबर से फोन काल की थी। सिर्फ एक कॉल करने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान एनएसएफ कॉलोनो के करण के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वारदात छह मई को देर रात विश्वास नगर इलाके में हुई थी, जब करन ने सूरज से शराब

● एक फोन कॉल से दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गुजरात से पकड़ा

की बोतल छीनने की कोशिश। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी तभी सूरज का भाई राहुल वहां आ धमका और उसने करन को कई थप्पड़ मारे। पुलिस के मुताबिक बाद में रात करीब साढ़े 11 बजे जब राहुल घर लौट रहा था तब करन ने उसपर चाकू से कई बार हमला किया। राहुल को डॉ. हेडोवार अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

पहलवान विदेशी ओलम्पियन से जुटाएंगे समर्थन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करने की स्थिति में विदेशों के ओलंपिक पदक विजेताओं और खिलाड़ियों से संपर्क करके अपने आंदोलन को वैश्विक मंच पर ले जाने का फैसला किया है। पहलवानों ने सोमवार को कहा कि आंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला 21 मई के बाद लिया जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट सहित देश के चोटी के पहलवान बृजभूषण को गिरफ्तारी की



कनाट प्लेस में अपनी मांगों को लेकर मार्च करते अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट व अन्य। फोटो: रंजन डिमरी

मांग को लेकर पिछले 23 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बृजभूषण पर महिला पहलवानों का कथित रूप से यौन

ने कहा, हम इस प्रदर्शन को विश्व स्तर पर ले जाएंगे। हम अन्य देशों के ओलंपियन और ओलंपिक पदक विजेताओं से संपर्क करेंगे। पहलवानों ने कहा कि वह उन्हें पत्र लिखकर उनसे समर्थन मांगेंगे। इसके साथ ही आरोप लगाया कि रविवार की रात को कुछ लोगों ने उनके प्रदर्शन की छवि बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि प्रदर्शन स्थल पर पहलवानों का पीछा किया जा रहा है। विनेश ने कहा, कुछ लोगों ने हमारे प्रदर्शन में बाधा डालने की कोशिश की। पिछली बार ऐसा तब हुआ जब हम विरोध स्थल पर बिस्तर ला रहे थे। उन्होंने कहा, उनका पीछा किया जा रहा है। लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और तस्वीरें ले रहे हैं।

दुर्घटना संभावित इलाकों में सीसीटीवी लगाएं

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी की एक निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को निर्देश दिया है कि वह दुर्घटना-संभावित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नागरिक एजेंसी के साथ बैठक करें और उन स्थानों के साथ अधुनिक कैमरे लगाने के लिए गंभीर प्रयास करें। अदालत ने दिल्ली के शीर्ष पुलिस अधिकारी से उन सड़क दुर्घटनाओं को पृष्ठभूमि में यातायात प्रबंधन के विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसके परिणामस्वरूप लोगों की जान गई और चोटें आईं।

● निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को नागरिक एजेंसी के साथ बैठक करने को कहा

अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-आठ, रिंग रोड और धौला कुआं सहित विभिन्न दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों का संज्ञान लिया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिाकरण की पीटासीन अधिकारी शेफाली बरनाला

टंडन एक निरीक्षक विपिन कुमार को उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें एनएच-आठ, रिंग रोड और धौला कुआं में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नागरिक एजेंसी को निर्देश देने की मांग की गई थी। टंडन ने आठ मई को दिए अपने आदेश में कहा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को एनएच-आठ, रिंग रोड, धौला कुआं आदि स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नागरिक एजेंसी यांनी एनएचआर में वाणिज्य विभाग में अनुसूचित जनजाति के लिए एक रिक्ति थी, जो इस वर्ष शून्य हो गई है।

आईपीसीडब्ल्यू में आवंटन में विसंगतियों का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वूमन (आईपीसीडब्ल्यू) कॉलेज में आरक्षित श्रेणी में शिक्षक पदों के आवंटन में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कुलपति को पत्र लिखा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि गेस्टर में गड़बड़ी से विभिन्न विभागों में अनुसूचित जनजाति के तीन पद समाप्त हो गए। शिक्षकों के अनुसार वर्ष 2019 में वाणिज्य विभाग में अनुसूचित जनजाति के लिए एक रिक्ति थी, जो इस वर्ष शून्य हो गई है।

तीन मेट्रो स्टेशन पर एसीएलएस सुविधाओं की संभावना तलाशें

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और डीएमआरसी को कश्मीरी गेट, राजीव चौक, हौज खास में तीन प्रमुख इंटरचेंज मेट्रो स्टेशनों पर उन्नत कार्डिक लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस) सुविधाओं की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली सरकार और डीएमआरसी से

सुनवाई की तारीख से पहले रिपोर्ट आदिखल करने को कहा। डीएमआरसी के वकील ने कहा कि इन तीन इंटरचेंज स्टेशन पर एसीएलएस सुविधाएं स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध है। पीठ ने आठ मई के अपने आदेश में कहा, बयान के मद्देनजर, डीएमआरसी और दिल्ली सरकार के वकील को तीन प्रमुख इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन पर एसीएलएस सुविधा की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया जाता है।

अनजाने ऐतिहासिक स्थलों की सैर करेंगे स्कूली बच्चे

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली पर्यटन विभाग ने शिक्षा विभाग के सामने रखा प्रस्ताव

● पर्यटन विभाग स्कूलों में छात्रों के टूर और पिकनिक के लिए करता रहा है स्कूलों की मदद

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केजरीवाल सरकार अब स्कूल छात्रों के राष्ट्रीय राजधानी की बेहतरीन जगहों की सैर कराएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग जल्द ही शिक्षा विभाग से संपर्क करेगा। पर्यटन विभाग छात्रों को उन जगहों पर सैर के लिए ले जाएगा, जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। पहले भी पर्यटन



विभाग स्कूलों में छात्रों के लिए होने वाले टूर और पिकनिक के लिए स्कूलों की मदद करता रहा है। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वह स्कूलों से संपर्क कर इस बात की योजना बना रहे हैं कि क्या वो छात्रों को हमारे साथ ऐसी जगहों पर घूमने के लिए भेज सकते हैं, जहां वे अभी तक नहीं गए। मसलन, मिर्जा गालिब की हवेली, मुगल समय का चोर मीनार, बिजय मंडल, राजाओं की बावली, अधम खान का मकबरा और बड़े और छोटे खान का मकबरा शामिल। अधिकारी ने कहा कि मालचा महल में हान्टेड हेरिटेज वाक भी इसी

दाश शिक्वे पुस्तकालय में संग्रहालय का उद्घाटन 18 को

मुगलकालीन दाश शिक्वे पुस्तकालय भवन में स्थित विभाजन संग्रहालय का 18 मई को उद्घाटन किया जाएगा। इस संग्रहालय में 1947 की त्रासदी की कहानियां और सीमा के दोनों ओर लोगों की पीड़ा और आघात का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक टाउन हॉल में स्थित अमृतसर के विभाजन संग्रहालय के बाद यह दूसरा ऐसा संग्रहालय होगा। इसका उद्घाटन अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर होगा। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने आगामी संग्रहालय के बारे में बताते हुए एक ट्वीट किया।

प्लान का एक हिस्सा है। पर्यटन विभाग राजधानी के व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए गाइटेड टूर की भी व्यवस्था करेगा। देखो मेरी दिल्ली ऐप में व्यंजनों और पर्यटकों की मदद के लिए पर्यटन स्थलों के बारे में बताया है। वह लोगों को दिल्ली के व्यंजनों का लुफ्त उठाने के लिए भी जल्द ही गाइड करेंगे। विभाग पुरातत्व विभाग और कैब प्रदाता कंपनियों से भी संपर्क कर रही है। पर्यटन के लिहाज से दिल्ली के हॉटस्पॉट को दर्शाने वाले मैगजिन को तरजीह दी जा रही है। इन मैगजिनों की उपलब्धता शहर के होटलों में सुनिश्चित किया जा रहा है।

भीषण गर्मी से बुरा हाल, हल्की बारिश के आसार

● राजधानी में 19 तारीख तक तेज हवा के साथ बूदा-बांदी की संभावना, गर्मी से मिलेगी मामूली राहत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में तेज हवाओं के साथ-साथ हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर बूदाबांदी का पूर्वानुमान लगाया है। इससे शहर के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान



25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस अवधि का सामान्य तापमान है। आर्द्रता का स्तर 27 से 50 प्रतिशत के बीच रहा। आईएमडी के अनुसार, रात के समय एक या दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ छोटे पड़ने की संभावना है। दिन में कई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक या दो स्थानों पर दोपहर या शाम को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश

भी हो सकती है। बारिश के बावजूद गर्मी से अधिक राहत नहीं मिलेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार, 18 मई को राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि 19 मई को तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छोटे पड़ने की संभावना है।

भावानुसार मिलता है श्रीमद्भागवत कथा श्रवण का रसः योगी



● गोरखनाथ मंदिर में सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ में शामिल हुए मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/गोरखपुर

मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा पांच हजार वर्षों से मानव के उद्धार व मुक्ति की कथा बनकर सनातन संस्कृति को अनुप्राणित कर रही है। इस कथा का श्रवण जिस भाव से किया जाता है, सुनने वाले को उसी के अनुसार रस प्राप्त होता है। यह हमें गौरवशाली अतीत का एहसास करने वाली कथा भी है। श्रीमद्भागवत की कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होना दुर्लभ क्षण होता है। सौम्य योगी सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा

ज्ञानयज्ञ के शुभारंभ पर कथाव्यास व अन्य संतजन का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। 21 मई तक चलने वाली इस कथा का आयोजन मंदिर परिसर में बने नौ नवीन मंदिरों में वेद विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रथम दिन की कथा प्रारंभ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने व्यासपीठ की पूजा करने के बाद कहा कि वेद, पुराण, उपनिषद हमारी हज़ारों वर्षों की धाती को समेटे हुए हैं। ये पवित्र ग्रंथ जीवन के यथार्थ का ज्ञान कराते हुए हमें सदमार्ग की ओर ले जाते हैं। श्रीमद्भागवत की कथा से आनंद प्राप्ति के साथ ज्ञानवर्धन भी होता है। इस अवसर पर उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान गोरखनाथ की कृपा सब पर बनी रहे।

भगवान श्रीकृष्ण का शब्दमय विग्रह है श्रीमद्भागवतः स्वामी राघवाचार्य

इस अवसर पर अयोध्या से आए जगदुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य ने कहा कि श्रीमद्भागवत ग्रंथ भगवान श्रीकृष्ण का शब्दमय विग्रह है। उन्होंने अपनी दिव्यदृष्टि को

श्रीमद्भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया है। स्वामी राघवाचार्य ने कहा कि सही अर्थों में जो माया का मर्दन कर दे, वह श्रीमद्भागवत महापुराण है। अयोध्या से ही आए बड़े भक्तमाल के महंत अवधेशदास ने सनातन धर्म व संस्कृति के उन्मूलन में मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के कार्य की मुकूट से सरहना की। उन्होंने कहा कि आज गोरक्षपीठ का नाम पूर्व विश्व में जाना जाता है। श्रीमद्भागवत कथा का विधिवत रसपान कराने से पूर्व कथाव्यास, वृंदावन से पधारें डॉ श्याम सुंदर पाराशर ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज प्रदेश में धर्म-अध्यात्म, संस्कृति और राजसत्ता, दोनों ही क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। अब तो अन्य प्रांतों के नागरिक भी अपने प्रांत में योगी जैसा नेतृत्व चाहते हैं।

मंदिर के गर्भगृह से निकाली गईं भव्य शोभायात्रा- श्रीमद्भागवत महापुराण कथा

शुभारंभ के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। गर्भगृह में मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी

बाल श्रद्धालु को देख रुक गए सीएम, प्रसाद देकर पूजा हालचाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/गोरखपुर

व्यस्तता कितनी भी हो, कार्य राजकीय हो या फिर धार्मिक-आध्यात्मिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को अपने स्नेह से अभिषिंचित करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। आनुष्ठानिक कार्यक्रमों की उनकी व्यस्तता के बीच सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में वृहद् धार्मिक-आध्यात्मिक कार्यक्रमों की शृंखला में सोमवार पूर्वाह्न मंदिर की यज्ञशाला में कलाश स्थापना व पंचांग पूजन करने के बाद गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने मुख्य मंदिर की तरफ जा रहे थे। थोड़ी दूर बढ़ते ही उनकी नजर धूप में खड़ी एक नन्ही बच्ची पर पड़ गई। वह तुरंत बालिका के पास ही रुक गए। मुख्यमंत्री का संकेत पाते ही साथ में मौजूद मंदिर के कार्यकर्ता अमित सिंह मोनू ने धूप से बचाने के लिए बालिका को उठा लिया। मुख्यमंत्री ने बालिका से उसका हालचाल पूछा, दुलारा और अपने हाथों से प्रसाद देकर खूब आशीर्वाद दिया। सीएम के यह पृष्ठन पर कि धूप में क्यों खड़ी थी? बालिका ने मासूमियत से कहा, आपको देखने के लिए। इस पर मुख्यमंत्री हंस पड़े, साथ ही प्यार से समझाया कि बच्चों को तेज धूप से बचना चाहिए।



आदित्यनाथ ने विधि विधान से श्रीनाथ, अखंड ज्योति एवं पोथी (श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ) पूजन का अनुष्ठान संपन्न किया। तत्पश्चात शंख, घंटा-घंड़ियाल, तुहरी, नागफनी आदि वाद्य यंत्रों की गूंज एवं बैंड बाजे के बीच शोभायात्रा कथा स्थल महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन पहुंची। यहां वैदिक मंत्रोच्चार व बीच व्यासपीठ के समक्ष अखंड ज्योति व श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ को प्रतिष्ठित किया गया। मुख्यमंत्री, संतो व यजमानगण ने व्यासपीठ का पूजन व कथाव्यास का अभिर्नंदन किया। भक्ति भाव से निकाली गई शोभायात्रा में मुख्य रूप से कथा व्यास श्रीधाम वृंदावन के डॉ श्याम सुंदर पाराशर, अयोध्या से पधारें जगदुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य, बड़े भक्तमाल अयोध्या के महंत अवधेशदास, कटक (ओडिशा) से आए महंत शिवनाथ, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, काशी से आए महंतमंजुेश्वर, संतोष दास सतुआ बाबा, देवीपाटन के महंत योगी मिथलेशनाथ, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्रदास, चचाईराम मठ के महंत पंचानन पुरी, श्रीरामजानकी ननुमान मंदिर गोरखनाथ के महंत रामदास, नवनिर्वाचित महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव आदि सम्मिलित रहे।

बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में चलेगा स्पोर्ट्स फार स्कूल कार्यक्रम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अश्वीन संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने व खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स फार स्कूल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी

कर दिया है।

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए छात्रों को शारीरिक गतिविधियों एवं खेलों से जोड़ने के साथ ही बालिकाओं को खेलों में प्रतिभाग के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाय। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय शिक्षकों को खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को आयोजन हेतु नोडल शिक्षक नामित किया जाय। जबकि जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए और स्तर पर रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग के लिए मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को नोडल ऑफिसर नामित किया जाय।

मुख्य सचिव ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सोमवार को एक समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मिश्र ने मेधावी छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अपने अपने परिश्रम व लगन से सर्वश्रेष्ठ परीक्षाफल देकर न सिर्फ अपने माता-पिता, शिक्षकों व विद्यालय का गौरव बढ़ाया है अपितु लखनऊ व प्रदेश का नाम भी रोशन किया है।

भाजपा सरकार ने अधिकारियों का राजनीतिकरण कर दिया: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अधिकारियों का राजनीतिकरण कर दिया है। बड़ी संख्या में अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता बन कर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने वोटर लिस्ट से लेकर मतगणना तक में हस्तक्षेप किया। अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी और बेबर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सीडीओ व अन्य अधिकारियों द्वारा चुनाव नतीजे बदले जाने की खबर से जनक्रोध है। इसका तुरन्त संज्ञान लिया जाय। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का निलम्बन किया जाय। साथ ही फास्ट ट्रैक जांच कर नौकरी से बाहर किया जाए। समाजवादी पार्टी इन भ्रष्ट अधिकारियों

पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ना सट्टा व आपूर्ति नीति जारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसेरुड़ी द्वारा पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी गई है। गन्ना आपूर्ति नीति के आधार पर ही प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ने की पंक्तियों के निर्गमन सहित आपूर्ति हेतु विस्तृत निर्देश चीनी मिलों को दिये हैं। सट्टा एवं आपूर्ति नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए भूसेरुड़ी ने बताया कि प्रदेश की चीनी मिलों की खराब क्षमता, गन्ना उत्पादन तथा चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता में संतुलन बनाये जाने की आवश्यकता है, जिससे चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पेरार्प हेतु गन्ना उपलब्ध हो सके। इन्होंने सब तथ्यों का संज्ञान लेते हुए गन्ना विकास विभाग द्वारा जारी पेराई सत्र 2023-24 के

लिये सट्टा एवं आपूर्ति नीति में कृषक हितों के दृष्टिगत कई बदलाव किये गये हैं, जिनमें मुख्य रूप से गन्ना कृषकों की बढ़ रही उपज के दृष्टिगत प्रति हेक्टेयर सट्टे की सीमा में सार्थक बढ़ोत्तरी की गई है। इस वर्ष की आपूर्ति नीति में प्रति कृषक गन्ना सट्टे की सीमा सीमान्त कृषक (1 हेक्टेयर तक) के लिए अधिकतम 850 कु.से बढ़कर 900 कु., लघु कृषक (2 हेक्टेयर तक) के लिये 1700 कु.से बढ़कर 1800 कु. तथा सामान्य कृषक (5 हेक्टेयर तक) के लिये 4250 कु. से बढ़कर 4500 कु.की गई एवं उपज बढ़ोत्तरी की दशा में सट्टे की अधिकतम सीमा सीमान्त, लघु एवं सामान्य कृषक हेतु क्रमशः 1350 कु. से बढ़कर 1400 कु., 2700 कु. से बढ़कर 2800 कु. तथा 6750 कु. से बढ़कर 7000 कु. निर्धारित की गई है। गन्ना किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग

लिये सट्टा एवं आपूर्ति नीति में कृषक हितों के दृष्टिगत कई बदलाव किये गये हैं, जिनमें मुख्य रूप से गन्ना कृषकों की बढ़ रही उपज के दृष्टिगत प्रति हेक्टेयर सट्टे की सीमा में सार्थक बढ़ोत्तरी की गई है। इस वर्ष की आपूर्ति नीति में प्रति कृषक गन्ना सट्टे की सीमा सीमान्त कृषक (1 हेक्टेयर तक) के लिए अधिकतम 850 कु.से बढ़कर 900 कु., लघु कृषक (2 हेक्टेयर तक) के लिये 1700 कु.से बढ़कर 1800 कु. तथा सामान्य कृषक (5 हेक्टेयर तक) के लिये 4250 कु. से बढ़कर 4500 कु.की गई एवं उपज बढ़ोत्तरी की दशा में सट्टे की अधिकतम सीमा सीमान्त, लघु एवं सामान्य कृषक हेतु क्रमशः 1350 कु. से बढ़कर 1400 कु., 2700 कु. से बढ़कर 2800 कु. तथा 6750 कु. से बढ़कर 7000 कु. निर्धारित की गई है। गन्ना किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग

● 60 की जगह अब 72 कुंतल के सट्टाधारक माने जायेगे छोटे किसान

● उपज के दृष्टिगत प्रति हेक्टेयर सट्टे की सीमा में की गई बढ़ोतरी

पर सम्यक विचारोंपरान्त गन्ना आयुक्त ने छोटे किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब 60 कुन्तल की जगह 72 कुन्तल तक के सट्टा धारक गन्ना किसानों को छोटे कृषक की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इससे इन सट्टा धारकों को 45 दिन के अन्दर गन्ना आपूर्ति की सुविधा मिल सकेगी। इस वर्ष की सट्टा आपूर्ति में भूमि क्रय-विक्रय के प्रकरणों में बेसिक कोटा हस्तान्तरण ट्रिप विधि से सिंचाई करने वाले

प्रचंड जीत के बाद भाजपा क्षेत्रीय स्तर पर करेगी बैठकें

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों के लेकर क्षेत्र स्तर पर बैठकें करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी व प्रदेश महामंत्री संगठन अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने आगामी 17, 18 व 19 मई को क्षेत्र स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला ने बताया कि भाजपा द्वारा संगठनात्मक दृष्टि से बनाए गए सभी 6 क्षेत्रों अवध, काशी, गोरखपुर, कानपुर बुंदेलखंड, ब्रज, पश्चिम में 17, 18 व 19 मई को क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 17 मई को पश्चिम व काशी क्षेत्र की बैठक होगी। जबकि 18 मई को ब्रज व गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी। कानपुर व कृषक क्षेत्र की बैठक 19 मई को होगी। गोविन्द नारायण शुक्ला ने बताया कि क्षेत्रीय बैठकों में पार्टी के क्षेत्र प्रभारी, क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय पदाधिकारी, उस क्षेत्र में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी व प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य, जिला प्रभारी जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक, नवनिर्वाचित महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।

● राधा मोहन सिंह सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा

निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों के लेकर क्षेत्र स्तर पर बैठकें करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी व प्रदेश महामंत्री संगठन अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने आगामी 17, 18 व 19 मई को क्षेत्र स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला ने बताया कि भाजपा द्वारा संगठनात्मक दृष्टि से बनाए गए सभी 6 क्षेत्रों अवध, काशी, गोरखपुर, कानपुर बुंदेलखंड, ब्रज, पश्चिम में 17, 18 व 19 मई को क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 17 मई को पश्चिम व काशी क्षेत्र की बैठक होगी। जबकि 18 मई को ब्रज व गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी। कानपुर व कृषक क्षेत्र की बैठक 19 मई को होगी। गोविन्द नारायण शुक्ला ने बताया कि क्षेत्रीय बैठकों में पार्टी के क्षेत्र प्रभारी, क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय पदाधिकारी, उस क्षेत्र में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी व प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य, जिला प्रभारी जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक, नवनिर्वाचित महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।

जन समस्याओं का त्वरित गति से किया जाए निदान : केशव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने 7.कालीदास मार्ग स्थित आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आये लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया।

उन्होंने जनसुनावई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।



से निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दर्शन में भूमि विवाद, दुर्घटनाओं से संबंधित, अवैध कब्जे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आवंटन, स्कूल निर्माण, भूमि पट्टा, कब्जा दिलाने, अतिक्रमण हटाने, सड़क बनवाने, विजली, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराने, आदि से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्रदेश की विभिन्न जिलों से आए लोगों ने रखी। जनता दर्शन में प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, जौनपुर,

गोंडा, मिर्जापुर, झांसी, कासगंज सहित लगभग ढाई दर्जन से अधिक जिलों से कई सैकड़ लोगों ने आकर अपनी समस्याएं रखीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्याओं के निस्तारण के बावत प्रतापगढ़, अम्बेडकरनगर सहित अन्य कई जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक कर्जोजए अन्य सम्बंधित उच्चाधिकारियों व शासन के उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर बातों की।

प्रदेश में चुनी गईं बीजेपी की आधा दर्जन महिला महापौर

● राजनीति में आधी आबादी का सपना साकार कर रही योगी सरकार

● सर्वाधिक वोट लखनऊ की सुषमा को तो सबसे बड़ी जीत गाजियाबाद की सुनीता के नाम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार का मिशन शक्ति अभियान न सिर्फ समाज बल्कि राजनीति में भी आधी आबादी का सपना सच कर रहा है। विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, हर चुनावों में महिलाओं को पूरी शक्ति देकर योगी सरकार ने नेतृत्व करने का गौरव प्रदान किया। यूपी के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद पर छह प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इन सभी ने जीत हासिल कर पहला नागरिक बनने का गौरव हासिल किया। परीक्षा परिणामों की तरह ही महापौर चुनाव में भी सबसे अधिक वोट पाने वाली और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली भी महिला ही रहीं। वहीं नगर पालिका के 44

भाजपा की 44 महिलाओं के हाथ नगर पालिका की कमान नगर पालिका परिषद की 199 सीटों में से 198 का परिणाम आ गया। इसमें से 88 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 88 में से 44 सीटों की कमान महिला अध्यक्षों के हाथ में आई। सीएम योगी की अपील रंग लाई। अमेठी, अमरौहा, उन्नाव, कन्नौज, कुशीनगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशांबी, गाजीपुर, गोंडा, नोएडा, जालौन, जौनपुर, झांसी, देवरिया, फतेहपुर, बलारामपुर, बहराइच, बागपत, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, रामपुर, ललितपुरए बिजनौर, सोनभद्र व हाथरस की एक-एक, एटा, पीलीभीत, फिरोजाबाद, बरेली, सीतापुर, बांदा की दो-दो, बदायूं, बुलंदशहर की तीन-तीन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की सीटों पर भाजपा की तरफ से महिलाओं ने जीत हासिल की। व 90 नगर पंचायतों की कमान भी महिलाओं के हाथ रही। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाई गई अल्पसंख्यक वर्ग की हकीकुन निशा ने बाबा गंभीर नाथ वॉर्ड से 2227 वोट पाकर विजय

भाजपा की 90 महिलाएं बनीं नगर पंचायत अध्यक्ष इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भी महिलाओं पर दांव लगाया। नगर पंचायत की 544 में से 543 सीटों पर चुनाव परिणाम आए। इनमें से 191 सीटों पर कमल खिल्ला तो 90 पर महिलाएं जीतने में कामयाब रहीं। अमेठी, अमरौहा, अयोध्या, आजमगढ़, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, कौशांबी, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, संतकबीर नगर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, गाजीपुर, नोएडा, चंडौली, बांदा, बाराबंकी, भदोही, फर्रुखाबाद, मेरठ, हरदोई, हाथरस, महाराजगंज जिले में एक-एक, मुरादाबाद, हमीरपुर, कानपुर देहात, कासगंज, जौनपुर, शाहजहांपुर, गोंडा, सभल, सहारनपुर में दो-दो, आगरा, गोरखपुर, जालौन, अलीगढ़, देवरिया, फतेहपुर, बलिया, बांसी, मैनपुरी, रायबरेली, फिरोजाबाद में तीन-तीन कुशीनगर-प्रतापगढ़ में चार, बदायूं में पांच सीटों पर भाजपा की ओर से महिलाओं ने जीत हासिल की। पताका फहरा दी। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में महापौर की 17 में से छह सीटों पर महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा। इन सभी छह सीटों पर भाजपा को जीत मिली। इन सभी सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। राजधानी लखनऊ से सुषमा खर्कवाल, आगरा से हेमलता दिवाकर, फिरोजाबाद से कामिनी राठी, कानपुर से प्रमिला पांडेय, गाजियाबाद से सुनीता दयाल व शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को पहला नागरिक बनने का गौरव हासिल हुआ। गाजियाबाद की सुनीता दयाल सबसे अधिक वोटों से महापौर बनीं। सुनीता ने 2.87 लाख से अधिक वोटों से बसपा प्रत्याशी को शिकस्त दी। लखनऊ की सुषमा खर्कवाल को पांच लाख से अधिक वोट मिले। आगरा से अब तक की सबसे बड़ी जीत भी महिला महापौर हेमलता दिवाकर के नाम रही। उन्होंने बसपा की 1.08 लाख से अधिक वोटों से हराया। कानपुर की प्रमिला पांडेय ने 1.77 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। शाहजहांपुर की अर्चना वर्मा ने 30 हजार व फिरोजाबाद की कामिनी राठी भी 26 हजार से अधिक वोटों से जीत का स्वाद चखा।

अक्षम विधार्थि मसौदा कर सकता है लोकतंत्र कमजोर

भाषा । नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि अक्षम विधार्थि मसौदा प्रणाली कानूनों एवं लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है और यहां तक कि न्यायपालिका के कामकाज को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि मसौदे में ग्रे ऐरिया (जहां कमी मिलने की गुंजाइश हो) से व्याख्या में अतिक्रमण की आशंका रहती है।



स्पष्ट मसौदे से न्यायिक अतिक्रमण की संभावना भी दूर रहती है। मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में जितनी

शाह ने कहा कि भारत न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र का विचार भी भारत से ही उभरा था। उन्होंने कहा कि महाभारत के दिनों से मौर्य युग तक और फिर गुप्त साम्राज्य तक, लोकतंत्र सरकारी प्रणालियों के विकल्पों में से एक था। गृह मंत्री ने कहा, भारतीय संविधान लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांतों और प्रथाओं द्वारा निर्देशित रहते हुए हमारी लोकतांत्रिक विरासत से बहुत अधिक प्रेरित है।

उन्होंने कहा कि विधायिका कानूनी विशेषज्ञों की संस्था नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की संस्था है जो लोगों की समस्याओं और आकांक्षाओं से अवगत हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वे लोगों के अनुसार कानून बनाते हैं लेकिन इन कानूनों को संविधान की भावना के अनुसार ढालना एक बड़ी जिम्मेदारी है जो विधार्थि विभाग पर है। शाह ने कहा कि कमियों की गुंजाइश नहीं छोड़ने

पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए...उदाहरण के लिए, संविधान का मसौदा तैयार करते समय, विषय सूची में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था। उन्होंने पूछा, अगर यह नहीं लिखा होता तो क्या होता? शाह ने कहा, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि किसी भी कानून का मसौदा तैयार करते समय विधायिका की आकांक्षा को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकारों का सुचारू कामकाज विधार्थि मसौदों पर भी निर्भर करता है। मंत्री ने कहा कि कानून का मसौदा तैयार करते समय कई कारकों- संविधान, लोगों के रीति-रिवाज, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, शासन व्यवस्था की संरचना, समाज की प्रकृति, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय संबंधों- का ध्यान रखा जाना चाहिए।



पुणे में उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान (डीआईएटी) के 12वें दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना: न्यायालय

भाषा । नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 देश में उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करने के लिए है और उपभोक्ताओं के खिलाफ इसके प्रावधानों को व्याख्या करने का कोई भी तकनीकी दृष्टिकोण इसके पीछे के उद्देश्य को विफल कर देगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का एक प्रसंगीय उद्देश्य है और 2019 का कानून उपभोक्ताओं को बहुत ही लचीली प्रक्रिया प्रदान करके मंचों से संपर्क करने की सुविधा देता है। न्यायालय ने कहा, यह देश में उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करने के लिए है। उपभोक्ता के खिलाफ प्रावधानों को बनाने में कोई भी तकनीकी दृष्टिकोण अधिनियमन के पीछे के उद्देश्य के खिलाफ जाएगा।

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी के विनियमन (एचआरआरएस) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत पंजीकृत एक फ्लैट आवंटियों का संघ है, जबकि प्रतिवादी एक बिस्डर है जिसे आवास परियोजना के विकास का काम सौंपा गया है। अपने फैसले में, पीठ ने यह भी पाया कि एएसोसिएशन ने एनसीडीआरसी से संपर्क किया था और आरोप लगाया

अडाणी समूह के खिलाफ 2016 से जांच नहीं कर रहे : सेबी

भाषा । नई दिल्ली

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह 2016 से अडाणी समूह की जांच नहीं कर रहा था और उसने इस तरह के दावों को लेंकर सेबी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय मांग रहे बाजार नियामक ने अपने पहले के हलफनामों में 51 भारतीय फर्मों द्वारा ग्लोबल डिफॉजिटीरी स्पीड (जीडीआर) जारी किए जाने का उल्लेख करते हुए बताया था कि अडाणी समूह की कोई भी सूचीबद्ध कंपनियों में से नहीं थी। सेबी गौतम अडाणी के नेतृत्व वाले समूह द्वारा शेयर की कीमतों में हेरफेर के आरोपों की जांच कर रही है।

2016 से इस मामले में कोई जांच कर रही है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जनहित याचिकाओं और सेबी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने समय के विस्तार के मुद्दे को लेकर सेबी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। बाजार विनियामक की याचिका और जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई समय की कमी और अपराह्न तीन बजे विशेष पीठ के समक्ष कुछ मामलों को पूर्ण निर्धारित सुनवाई के कारण आज नहीं हो सकी। नियामक के ताजा हलफनामों में कहा गया कि सेबी द्वारा समय बढ़ाने के लिए दायर आवेदन का मतलब निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करना है, क्योंकि पूर्ण तथ्यात्मक सामग्री के बिना मामले का कोई भी गलत या समय से पहले निष्कर्ष न्याय

के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और इसलिए कानूनी रूप से अस्थिर होगा। उसने कहा कि इसके पहले के जवाबी हलफनामों में उल्लिखित जांच का हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित औद्योगिक उपन होने वाले मुद्दों से कोई संबंध नहीं है ...। हलफनामों में कहा गया, पैरा 5 में संदर्भित मामला 51 भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ग्लोबल डिफॉजिटीरी स्पीड जारी करने से संबंधित है, जिसके संबंध में जांच की गई थी। हालांकि, अडाणी समूह की कोई भी सूचीबद्ध कंपनी उपरोक्त 51 कंपनियों का हिस्सा नहीं थी। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की गई। इसने इस आरोप को तथ्यात्मक रूप से निराधार करार दिया कि सेबी 2016 से अडाणी समूह की जांच कर रहा है। सेबी ने कहा, इसलिए, कहता चाहता हूँ कि जीडीआर से संबंधित जांच पर भरोसा करने की मांग पूरी तरह से गलत है।

विवक न्यून

रक्षा आयात पर निर्भरता सामरिक स्वायत्तता में बाधा बन सकती है: राजनाथ सिंह

पुणे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। सिंह ने पुणे में उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान (डीआईएटी) के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता भारत की सामरिक स्वायत्तता में बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता के बिना, हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप वैश्विक मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। हम जितना अधिक उपकरण आयात करेंगे, उसका हमारे व्यापार संतुलन पर उतना अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम शुद्ध आयातक के बजाय शुद्ध निर्यातक बनने का लक्ष्य रखते हैं। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से अलगाव नहीं है। उन्होंने कहा, आज, दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है और अलग रहना संभव नहीं है। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य अपने मित्र देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपनी क्षमता से आवश्यक उपकरणालेडफर्मों बनाकर सशक्त बलों को जरूरतों को पूरा करना है। न्हीं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की बात की, जिसमें सशस्त्र बलों के लिए चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की घोषणा शामिल है। इसमें 411 प्रणालियां/उपकरण शामिल हैं। सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा नवाचार के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जा रहा है, भारत स्टार्ट-अप के लिए दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय को लगातार नवोन्मेषी विचार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज के पिछले सात संस्करणों में 6,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो इंगित करता है कि भारतीय स्टार्ट-अप रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तलाश में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अधिक पेटेंट दायर किए जा रहे हैं, जो अभिनव कोशल का संकेत है।

मांरिथस के राष्ट्रपति ने बेलूर मठ व दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन किए

कोलकाता। मंरीथस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन कोलकाता की तीन दिवसीय निजी यात्रा के दौरान सोमवार को आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थलों बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के एक प्रवक्ता ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अपनी पत्नी के साथ रूपन ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा की और कहा कि वह अभिभूत हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद वह रामकृष्ण मठ एवं मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और सांस्कृतिक संगठन खोला हवा के अध्यक्ष स्वप्न दासगुला रूपन के साथ थे। रूपन रविवार सुबह कोलकाता पहुंचे थे।

एनआईए ने जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे

श्रीनगर। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) ने जम्मू कश्मीर में शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे आतंकी संगठनों एवं उनके सहयोगी संगठनों पर कार्रवाई के तहत सोमवार को घाटी में 13 स्थानों पर छापे मारे। एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और बडगाम जिलों में छापे मारे गए और छापे के दौरान अभियोजन घाय्य सामग्री एवं दस्तावेज जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल बद्र, और अलकायदा समेत पाकिस्तान आधारित कई आतंकवादी संगठनों से संबद्ध नए संगठनों, उनसे सहायुभूत रखने वालों, उनके लिए काम करने वाले या कर चुके लोगों के 13 स्थानीय/ठिकानों पर सघन तलाशी शुरू की। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ए छापे द रिसर्च प्रंट (टीआरएफ), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर, मुजाहिदीन गजबत-उल-हिंद, जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर टाइगर, पीएएफ जैसे कई नए संगठनों के लिए काम कर रहे वाले लोगों की गतिविधियों, उनकी आतंकी साक्षिण की मौजूदा एनआईए जांच का हिस्सा है। एनआईए ने कहा कि ए लोग आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों के अलावा चूंचक बन, आईईडी, धन, स्वतंत्र गवाह के प्रति अतुचित व्यवहार एवं वितरण में भी शामिल पाए गए हैं। इसने कहा कि उसकी जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी और उनके सहयोगी ड्रोन के माध्यम से कश्मीर में संबंधित लोगों तक हथियार, गोला-बारूद और मादक पदार्थ पहुंचाते हैं तथा इस काम में सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। एनआईए ने पिछले साल स्वतः सज्जन लेते हुए 21 जून को मामला दर्ज किया था।

वानखेड़े की विदेश यात्राएं, कीमती घड़ियां जांच के दायरे में

नई दिल्ली। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की विदेश यात्राएं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीआई ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित तौर पर मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसा देने के लिए उनके परिवार से 25 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगने को लेकर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एनसीबी के विशेष जांच दल (एसईटी) ने विभाग के तत्कालीन जोनल निदेशक वानखेड़े की विदेश यात्राओं पर उनके कथित अनुचित जवाबों तथा खर्चों पर स्पष्ट तौर पर गलत जानकारी को लेकर संदेह बताया था। एसईटी ने अपनी जांच में कहा, उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के स्रोत के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। ऐसा पाया गया कि वानखेड़े विभाग (वर्तमान तथा मूल) को सूचित किए बिना विरल राजन नामक व्यक्ति के साथ मंहगो घंटियों की बिक्री और खरीद में लिप्त थे। एसईटी की जांच में सामने आई बातों को प्राथमिकी में शामिल किया गया है। सोमवार को सर्वजनिक किए गए प्राथमिकी के व्यौरों के अनुसार, स्वतंत्र गवाह के पी गोसावी तथा प्रभाकर सैल को वानखेड़े के निदेश पर कॉर्टेला क्रूज पोत पर दो अक्टूबर 2021 को मारे गए छापे में एनसीबी ने शामिल किया था। प्रभाकर सैल की मौत हो चुकी है। गोसावी ने अपने सहयोगी सांजिल डिस्जूजा तथा अन्य के साथ मिलकर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये की उगाही करने की साक्षिण रची थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आर्यन को छोड़ने के लिए गोसावी तथा डिस्जूजा ने राशि पर बातचीत की और इसे घटा कर 18 करोड़ रुपये किया। साथ ही उन्होंने 50 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर ले भी लिए, बाद में इसका कुछ हिस्सा लौट दिया था।

हरिवंश ने पुरानी पेंशन बहाली से पाकिस्तान और श्रीलंका सरीखे आर्थिक संकट के बारे में चेताया

भाषा । इंदौर

राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की स्थिति में देश की आर्थिक बहाली के खतरे की ओर सोमवार को आगाह किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए पुरानी पेंशन योजना पर लौटने का बात हो रही है, लेकिन समाज को बहस करनी चाहिए कि क्या ऐसे कदमों से भविष्य में देश में श्रीलंका और पाकिस्तान सरीखा धोषण आर्थिक संकट पैदा नहीं हो जाएगा?

हरिवंश ने कहा, अब सत्ता पाने के लिए वापस पुरानी पेंशन योजना पर जाने की बात हो रही है क्योंकि सरकारी कर्मचारी संगठित हैं और इस कारण यह एक बड़ा बोट बैंक है। उन्होंने कहा कि जिन पांच राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, उनके सरकारी खजाने पर कुल मिलाकर तीन लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया है। हरिवंश ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाले राज्यों में शामिल राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि इस कदम से राजस्थान के कुल कर राजस्व का 56 प्रतिशत हिस्सा केवल छह फ्रीसद सरकारी कर्मचारियों पर खर्च होगा। उन्होंने देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने पर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने के आसंकित दुष्परिणामों पर जोर देते हुए कहा, तो क्या हम भविष्य में अपने देश में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं?

तमिलनाडु में जहरीली शराब से जान गंवाने वालों की संख्या 14 हुई

भाषा । विल्लुपुरम (तमिलनाडु)

तमिलनाडु के विल्लुपुरम में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर सोमवार को 14 हो गई और 51 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। राज्य सरकार ने एक बयान में यह जानकारी दी। विल्लुपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने पत्रकारों से कहा कि मामले की जांच सीबी-सीआईडी (क्राइम-ब्रांच क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) को स्थानांतरित की जाएगी और उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार, शराब बनाने में मेथेनॉल का इस्तेमाल किए जाने के कारण यह त्रासदी हुई। अनाद्रमक प्रमुख एवं विपक्ष के नेता के. पलानीस्वामी ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु में अवैध शराब की बढ़ती उपलब्धता का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। अगर सरकार ने उचित कार्रवाई की होती तो ऐसी घटनाओं



अस्पताल में भर्ती लोगों का इलाज करते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को टाला जा सकता था। उन्होंने तिरुचिरापल्ली में पत्रकारों से कहा, मुख्यमंत्री स्टालिन पूरी तरह से (इसके लिए) जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वह एक अयोग्य मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ द्रमुक की आलोचना की। स्टालिन ने कहा कि चेंगलपेट जिले के पेस्कूरनाई गांव में अवैध शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई और सात लोगों का चेंगलपेट सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। विल्लुपुरम और चेंगलपेट में अवैध शराब बनाने के लिए ए थे नॉल का इस्तेमाल किया गया। अवैध शराब को भरने के लिए चेंगलपेट में राज्य द्वारा संचालित टीएएसएमएसी दुकान में बेचे जाने वाले मादक पेय पदार्थों

हिंदुत्व धर्म नहीं, बजरंग दल गुंडों की टोली: दिग्विजय

भाषा । जबलपुर (मप्र)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है और वह सनातन धर्म में विश्वास करते हैं जो सद्भाव और सभी के कल्याण का उपदेश देता है। कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य को यहाँ पत्रकार वार्ता में बजरंग दल (विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा) को गुंडों की जमात करार दिया। सिंह ने एक सवाल के उत्तर में कहा, हमारा सनातन धर्म है। हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो जैसे नारे सनातन धर्म की सभाओं का प्रतीक हैं। यह सनातन धर्म है। उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन हिंदुत्व के साथ ऐसा नहीं है। हिंदुत्व है- जो नहीं माने उन्हें डंडों से मारो, उनके घरों को तोड़ दो, पैसे उड़ाओ। सिंह ने कहा कि यह दुर्घटना है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, गुंडों की जमात ने जबलपुर में कांग्रेस कमेटी कार्यालय (चार मई को) में तोड़फूड़ करने के लिए हमला

किया था। उन्होंने कहा कि बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करना देवता का अपमान करने के समान है। उन्होंने आगे कहा, आर्यकी क्षमा मांगनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके सिंह ने कहा कि कांग्रेस संविधान, नियमों और कानूनों का पालन करती है। कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के चुनावी वादे के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने नफरत फैलाने वाले

ईडी को रायपुर के महापौर के भाई की 21 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन का पता चला

छत्तीसगढ़ शराब डोटाला

भाषा । नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट घोटाला मामले में कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज देवर के बड़े भाई अन्वर देवर द्वारा कथित रूप से अधिगृहीत 21 करोड़ रुपये से अधिक की भूमि का खुलासा किया है।

राज्य के आबकारी विभाग में विशेष सचिव का भी प्रभार था। अन्वर देवर, होटल कारोबारी नितेश पुरोहित और शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह हिल्लों को एजेंसी ने अपनी जांच के तहत हिरासत में ले लिया है। चारों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एक बयान में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा

कि छत्तीसगढ़ के रायपुर व भिलाई तथा मुंबई में हालिया दौर के छापों के फलस्वरूप एक जेबी (संयुक्त उपक्रम) के नाम पर अपराध की आय का उपयोग करके अन्वर देबर द्वारा नया रायपुर में अधिग्रहित 53 एकड़ भूमि (21.60 करोड़ रुपये कीमत) का पता लगाया गया।

ईडी ने लॉटरी किंग सैटियागो मार्टिन से संबंधित मामले में 457 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

संघीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में यह आरोप भी लगाया कि छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएएसएमसीएल) के प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी ने अन्वर देबर के कहने पर छत्तीसगढ़ के समूचे शराब तंत्र को ध्वस्त किया। भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के अधिकारी त्रिपाठी इस मामले में ईडी द्वारा पिछले हफ्ते गिरफ्तार चौथे व्यक्ति हैं। उनके पास

बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कांग्रेस का वादा क्या मुस्लिम मतों को लाभबंद करने की रणनीति थी ?

नई दिल्ली । (भाषा) । कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का वादा चुनावी घोषणापत्र में जानबूझकर शामिल किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस वादे का मकसद मुस्लिम मतों को अपने पक्ष में लाभबंद करना था? कांग्रेस के घोषणापत्र समिति में शामिल नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि इस मुद्दे को आखिरी मिनट पर घोषणापत्र में डाला गया, ताकि भाजपा इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सके। पार्टी ने गत दो मई को जारी अपने घोषणापत्र में कहा था, हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र है। कोई व्यक्ति या बजरंग दल, पीएफआई और नफरत एवं शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वह बहुसंख्यकों के बीच के हों या अल्पसंख्यकों के बीच के हों, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे।

